The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 2 | Issue 7 | July 2024
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और विकास

रूचि कुमारी
शोधार्थी, स्नातकोत्तर अर्थषास्त्र विभाग
तिलकामाँझी भागलपुर वि**श्व**विद्यालय, भागलपुर

डॉ. नाज परवीन
एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थषास्त्र विभाग
सबौर कॉलेज, सबौर**,** तिलकामाँझी भागलपुर वि**श्व**विद्यालय, भागलपुर

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Keywords: *किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि वित्त, बैंकिंग सुधार, कृषि विकास।*

ABSTRACT

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना का उद्देश्य भारतीय किसानों को सस्ती और त्वरित ऋण सुविधा प्रदान करना है। इस अनुसंधान पत्र में KCC योजना के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, विकास, और समय–समय पर किए गए सुधारों का गहन अध्ययन किया गया है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और देश की लगभग आधी आबादी की आजीविका का प्रमुख स्रोत है। कृषि उत्पादन और किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न योजनाएँ और नीतियाँ समय–समय पर लागू की जाती रही हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना है, जिसे 1998 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नाबार्ड (NABARD) द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य किसानों को त्वरित, सस्ती, और पर्याप्त ऋण सुविधा प्रदान करना है, ताकि वे अपनी कृषि और संबद्ध गतिविधियों को सुचारू रूप से चला सकें।

परिचय (Introduction)

कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और यह देश की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करता है। किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नाबार्ड (NABARD) ने 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को विभिन्न कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से किसानों को खेती के विभिन्न चरणों, जैसे बीज, खाद, कीटनाशक, और फसल कटाई के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके

अलावा, यह योजना पशुपालन, मछली पालन, बागवानी, और अन्य गैर–फसली गतिविधियों के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। KCC योजना का प्रमुख उद्देश्य किसानों को साहूकारों और अनौपचारिक ऋणदाताओं पर निर्भरता से मुक्त करना और उन्हें संगठित बैंकिंग प्रणाली में शामिल करना है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना की प्रासंगिकता और महत्व को देखते हुए, इस अनुसंधान पत्र का उद्देश्य योजना के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, विकास, और समय–समय पर किए गए सुधारों का विश्लेषण करना है। इसके अतिरिक्त, अध्ययन में KCC योजना के प्रभाव, चुनौतियों, और संभावनाओं का भी विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन KCC योजना की सफलता और इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करता है, जो भारतीय कृषि और बैंकिंग क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस अनुसंधान के माध्यम से KCC योजना की वर्तमान स्थिति और इसके सुधार के लिए आवश्यक कदमों की पहचान की जाएगी, ताकि यह योजना और अधिक सफल हो सके।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का महत्वः

KCC योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए समय पर ऋण उपलब्ध कराना है। यह योजना किसानों को खेती के विभिन्न चरणों में आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह किसानों को अनौपचारिक ऋणदाताओं और साहूकारों की जकड़ से मुक्त करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर किसान उच्च ब्याज दरों पर अनौपचारिक ऋणदाताओं से ऋण लेते हैं, जिससे वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। KCC योजना के तहत, किसानों को संगठित बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से ऋण मिलता है, जो न केवल सुरक्षित है, बल्कि ब्याज दरें भी अपेक्षाकृत कम होती हैं। इससे किसानों की वित्तीय स्थिति मजबूत होती है और वे अपने कृषि कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

इसके अलावा, KCC योजना में समय–समय पर किए गए सुधारों ने इसके महत्व को और बढ़ाया है। 2004 में पशुपालन और मछली पालन को शामिल करने से लेकर 2018 में बागवानी और अन्य गैर–फसली गतिविधियों के लिए ऋण सुविधा प्रदान करने तक, इन सुधारों ने योजना को अधिक समावेशी और व्यापक बनाया है। डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार भी KCC योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिससे ऋण प्रक्रिया में तेजी और सरलता आई है। इन सुधारों ने किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारतीय कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान दिया है।

अध्ययन की प्रासंगिकताः

इस अध्ययन का उद्देश्य KCC योजना के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करना है, जिसमें इसके ऐतिहासिक विकास, सुधार, और वर्तमान स्थिति शामिल हैं। यह अध्ययन KCC योजना के प्रभाव और इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों का भी विश्लेषण करता है।

साहित्य समीक्षा (Review of Literature)

शर्मा, आर. (2016), इस अध्ययन में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के प्रभाव का विश्लेषण किया गया। शर्मा ने पाया कि KCC योजना ने किसानों को त्वरित और सस्ती ऋण सुविधा प्रदान की है, जिससे उनकी कृषि उत्पादकता और वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। अध्ययन में यह भी उल्लेख किया गया है कि योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कुछ सुधार आवश्यक हैं।

सिंह, ए. (2018), इस शोध ने KCC योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार का अध्ययन किया। सिंह ने पाया कि डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं, जैसे एटीएम कार्ड और मोबाइल बैंकिंग, के माध्यम से किसानों को ऋण प्रक्रिया में सरलता और त्वरितता मिली है। इसने किसानों की बैंकिंग प्रणाली में विश्वास को बढ़ाया है और उनकी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है।

वर्मा, पी. (2020), वर्मा के अध्ययन ने KCC योजना के तहत ऋण वितरण के पैटर्न का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि योजना के तहत दी जाने वाली ऋण राशि में समय के साथ वृद्धि हुई है, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अभी भी जागरूकता की कमी है। वर्मा ने सुझाव दिया कि सरकार और बैंकिंग संस्थानों को जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाने चाहिए।

गुप्ता, एस. (2021), गुप्ता ने KCC योजना के विभिन्न सुधारों और उनके प्रभावों का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि 2004, 2012, और 2018 में किए गए सुधारों ने योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाया है और किसानों की विभिन्न कृषि गतिविधियों के लिए ऋण की सुविधा प्रदान की है। गुप्ता ने यह भी सुझाव दिया कि योजना में और सुधार की गुंजाइश है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके।

मेहता, आर. (2023), इस हालिया अध्ययन ने KCC योजना की वर्तमान स्थिति और इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण किया। मेहता ने पाया कि योजना के तहत किसानों को त्वरित ऋण सुविधा मिल रही है, लेकिन ऋण प्रक्रिया की जटिलता और जागरूकता की कमी अभी भी एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने सुझाव दिया कि योजना की प्रक्रिया को और सरल और त्वरित बनाने के लिए डिजिटल तकनीकों का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए।

संबंधित सिद्धांत और मॉडलः

कई मॉडल और सिद्धांत KCC योजना की प्रभावशीलता का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किए गए हैं। इन सिद्धांतों में कृषि वित्त, बैंकिंग सुधार, और विकास अर्थशास्त्र शामिल हैं।

अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study)

1. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करना।
2. योजना के विकास और सुधारों का विश्लेषण करना।
3. KCC योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
4. योजना की चुनौतियों और संभावनाओं का विश्लेषण करना।

कार्यप्रणाली (Methodology)

अनुसंधान डिजाइन: यह अध्ययन एक वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक अनुसंधान डिजाइन का पालन करता है।

डेटा संग्रहण विधियाँ: अध्ययन के लिए द्वितीयक डेटा का उपयोग किया गया है। इसमें सरकारी रिपोर्ट, शोध पत्र, और अन्य संबंधित साहित्य शामिल हैं।

डेटा विश्लेषण तकनीकें: संग्रहित डेटा का विश्लेषण सांख्यिकीय तकनीकों और वर्णनात्मक विश्लेषण के माध्यम से किया गया है।

अध्ययन का पृष्ठभूमि (Background of the Study)

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का इतिहास: KCC योजना की शुरुआत 1998 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नाबार्ड (NABARD) द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को सस्ती और त्वरित ऋण सुविधा प्रदान करना था।

योजना के प्रारंभिक चरण में, KCC केवल फसल ऋण के लिए उपलब्ध था। किसानों को उनकी कृषि आवश्यकताओं के अनुसार ऋण की एक निश्चित सीमा दी जाती थी, जिसे वे अपनी फसल की अवधि के दौरान उपयोग कर सकते थे। इस ऋण का उपयोग बीज, खाद, कीटनाशक, और अन्य कृषि इनपुट्स के लिए किया जा सकता था। योजना का मुख्य लाभ यह था कि किसान अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आवश्यकता अनुसार ऋण राशि का उपयोग कर सकते थे और उन्हें ब्याज केवल उपयोग की गई राशि पर ही देना होता था।

समय के साथ, KCC योजना में कई महत्वपूर्ण सुधार और विस्तार किए गए। 2004 में, पशुपालन और मछली पालन को योजना में शामिल किया गया, जिससे किसानों को विभिन्न कृषि संबद्ध गतिविधियों के लिए भी ऋण मिलना शुरू हुआ। यह कदम किसानों की आय के स्रोतों में विविधता लाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। इसके बाद, 2012 में डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं को योजना में जोड़ा गया, जिससे किसानों को एटीएम कार्ड और मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाओं का लाभ मिला। इससे ऋण प्रक्रिया में और भी अधिक तेजी और सरलता आई।

2018 में, KCC योजना में बागवानी और अन्य गैर–फसली गतिविधियों के लिए भी ऋण की सुविधा प्रदान की गई। इस विस्तार ने योजना को और अधिक समावेशी बनाया और किसानों को उनकी विविध कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की। इन सुधारों ने KCC योजना की पहुंच और प्रभावशीलता को बढ़ाया है, जिससे अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सके। इन सभी सुधारों और विस्तारों के बावजूद, योजना के समक्ष कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और ऋण प्रक्रिया की जटिल होना।

योजना के विकास की प्रक्रिया:

1998 से लेकर अब तक KCC योजना में कई सुधार किए गए हैं। शुरूआती चरण में यह योजना केवल फसल ऋण के लिए थी, लेकिन समय के साथ इसमें अन्य कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए भी ऋण की सुविधा जोड़ी गई।

योजना में समय–समय पर किए गए सुधार:

- 2004: KCC योजना में पशुपालन और मछली पालन को शामिल किया गया।
- 2012: किसानों को एटीएम कार्ड और अन्य डिजिटल सुविधाओं का लाभ दिया गया।
- 2018: योजना में बागवानी और अन्य गैर–फसली गतिविधियों को भी शामिल किया गया।

योजना का विकास और सुधार (Development and Reforms in the Scheme)

प्रारंभिक चरण: 1998 में KCC योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से फसल ऋण की सुविधा प्रदान की जाती थी।

प्रमुख सुधार और उनके प्रभाव:

- **2004 के सुधार:** पशुपालन और मछली पालन को शामिल करने से किसानों को विविध कृषि गतिविधियों के लिए ऋण मिलना शुरू हुआ।
- **2012 के सुधार:** डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं के माध्यम से किसानों को त्वरित और सरल ऋण प्राप्त हुआ।
- **2018 के सुधार:** बागवानी और अन्य गैर–फसली गतिविधियों के लिए ऋण की सुविधा ने किसानों की आय में वृद्धि की।

सरकार और बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका

सरकार और बैंकिंग क्षेत्र ने KCC योजना के विकास और सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकारी नीतियों और बैंकों की सक्रिय भागीदारी ने इस योजना को सफल बनाने में मदद की है। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के सफल कार्यान्वयन में सरकार और बैंकिंग क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सरकार ने KCC योजना को मजबूत और व्यापक बनाने के लिए कई नीतिगत पहलें की हैं। इनमें समय–समय पर योजना के सुधार, नीतिगत

दिशानिर्देश जारी करना, और किसानों के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना शामिल है। बैंकिंग क्षेत्र ने इन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे किसानों को त्वरित और सस्ती ऋण सुविधा प्राप्त हो सकी है।

2012 में सरकार ने KCC योजना में डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं को शामिल करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य किसानों को एटीएम कार्ड और मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाओं का लाभ देना था, जिससे ऋण प्रक्रिया सरल और त्वरित हो सके। इस पहल का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला, और कई किसानों ने इन सुविधाओं का उपयोग करना शुरू किया। इससे न केवल ऋण प्रक्रिया में तेजी आई, बल्कि बैंकिंग प्रणाली में किसानों का विश्वास भी बढ़ा। इसके अलावा, सरकार ने विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के बारे में जानकारी बढ़ाई गई।

बैंकिंग क्षेत्र ने KCC योजना के तहत ऋण वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने किसानों को विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान किए, जैसे कि फसल ऋण, पशुपालन ऋण, और बागवानी ऋण। बैंकिंग क्षेत्र ने सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण वितरण प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने का प्रयास किया। इसके अलावा, बैंकों ने किसानों को ऋण संबंधी जानकारी और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष शिविरों और कार्यशालाओं का आयोजन किया।

सरकार और बैंकिंग क्षेत्र के प्रयासों के परिणामस्वरूप, KCC योजना के तहत ऋण वितरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नीचे दिए गए तालिका में 2012 से 2022 तक KCC योजना के तहत दी गई ऋण राशि और लाभार्थियों की संख्या का विवरण प्रस्तुत किया गया है:

सरकार और बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका: ऋण वितरण तालिका

वर्ष	ऋण राशि (करोड़ रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या (लाख में)
2012	1,50,000	70
2013	1,60,000	75
2014	1,70,000	80
2015	1,85,000	85
2016	2,00,000	90
2017	2,20,000	95
2018	2,50,000	100
2019	2,80,000	110
2020	3,00,000	120
2021	3,20,000	130

2022	3,50,000	140

स्रोतः भारतीय कृषि मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक रिपोर्ट्स (2012–2022)

सरकार और बैंकिंग क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों ने KCC योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाया है। इस योजना के तहत ऋण वितरण में लगातार वृद्धि ने किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार किया है और उनकी कृषि उत्पादकता में वृद्धि की है। सरकार की नीतिगत पहलें और बैंकिंग क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी ने सुनिश्चित किया है कि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकें। इन प्रयासों ने भारतीय कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह तालिका भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए समग्र आंकड़ों का उल्लेख करता है, जो किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के तहत दी गई ऋण राशि और लाभार्थियों की संख्या को दर्शाता है।

परिणाम और विश्लेषण (Results and Analysis)

एकत्रित डेटा का विश्लेषणः KCC योजना के तहत दी गई ऋण की मात्रा और वितरण के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। यह पाया गया कि योजना ने किसानों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- KCC योजना ने किसानों को त्वरित और सस्ती ऋण सुविधा प्रदान की है।
- समय–समय पर किए गए सुधारों ने योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाया है।
- डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं के माध्यम से ऋण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

निष्कर्ष (Conclusion)

KCC योजना ने भारतीय कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार लाए हैं। यह योजना किसानों को विभिन्न कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। KCC योजना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और विकास महत्वपूर्ण रहा है। समय–समय पर किए गए सुधारों ने योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाया है। योजना के समक्ष कुछ चुनौतियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद इसने कृषि क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव डाला है।

खोज और सुझाव (Findings and Suggestions)

1. KCC योजना ने किसानों को त्वरित और सस्ती ऋण सुविधा प्रदान की है।
2. समय–समय पर किए गए सुधारों ने योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाया है।
3. योजना के समक्ष कुछ चुनौतियाँ हैं, जैसे जागरूकता की कमी और प्रक्रिया की जटिलता।

कृषि और बैंकिंग क्षेत्र के लिए सुझावः

1. KCC योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं।
2. ऋण प्रक्रिया को और सरल और त्वरित बनाने के लिए डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाए।

3. किसानों की विभिन्न जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजना में और सुधार किए जाएं।

संदर्भ (References)

1. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI). (2020). किसान क्रेडिट कार्ड योजना. https%//www-rbi-org-in
2. नाबार्ड (NABARD). (2019). कृषि वित्त और किसान क्रेडिट कार्ड योजना. https%//www-nabard-org
3. कुमार, एस. (2018). भारतीय कृषि में वित्तीय सुधार. कृषि विकास जर्नल, 25(3), 45–60.
4. शर्मा, आर. (2016). किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रभाव. बैंकिंग रिसर्च जर्नल, 14(2), 123–138.
5. Singh, A. (2018). Expansion of Digital Banking Facilities under the Kisan Credit Card Scheme. Journal of Agricultural Economics, 27(3), 112-128.
6. Verma, P. (2020). Analysis of Loan Distribution Patterns under the Kisan Credit Card Scheme. Indian Journal of Rural Studies, 32(1), 45-59.
7. Gupta, S. (2021). Impact of Reforms in the Kisan Credit Card Scheme. Journal of Financial Development, 36(4), 78-94.
8. Mehta, R. (2023). Current Status and Challenges of the Kisan Credit Card Scheme. Journal of Agricultural Finance, 40(2), 155-172.
9. गोस्वामी, पी. (2015). कृषि क्षेत्र में वित्तीय सुधारः एक विश्लेषण. विकास अध्ययन जर्नल, 30(4), 89–102.
10. भारतीय कृषि मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक रिपोर्ट्स (2012–2022)